(b) No blue prints of the device were submitted to NRDC by the inventor while applying for the prize award.

Quality of research programmes

2128. SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the Comptroller and Auditor General's Report to Parliament in 1997 which raised questions not only about the quality and quantity of research programmes undertaken by research institutions, but also about the administrative competence and fiscal discipline of these institutions;

(b) whether several research institutions have allowed projects on hand to drag on for years, or wound up some of them mid-way, without assigning any reasons; and

(c) if so, the reaction of the Government thereto and the corrective measures taken in this regard?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Research projects entail high uncertainty and risks unlike developmental projects. Thus not only their administrative and fiscal management differs from that of developmental projects but also their continuance or otherwise depends on the intermediary outputs/results.

Different government R&D institutions adopt differeing mechanisms to review the outputs of research projects depending upon their special-endowments. For example in CSIR every laboratory has a Research Council (RC), having expert members drawn from industry, academia, R&D, government etc. which review and recommend further course of action on projects. CSIR has further strengthened the monitoring of research projects in the laboratories by requiring every laboratory to review and monitor their ongoing projects annually in April for their continuance or otherwise, especially of projects continuing for more than 3 years; and any project to be continued beyond 5 years requires special approval.

12 NOON

STATEMENT BY MINISTER

Correcting the reply given in the Rajya Sabha on the 12th June, 1998 to the Starred Question 248 regarding Development of Science

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): Sir, on 12th June, 1998 Shri Raj Babbar raised a question. His question was:

> "Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:
>
> (a) whether it is a fact that the Prime Minister has given a slogan of Jai vigyan'; and
>
> (b) if so, the steps being taken by Government for the development of science?"

The answer was: "(a) Yes Sir.

(b) The Prime Minister during his speech at the Shanti Swaroop Bhatnagar Prize distribution function held on the 25th May, 1998 outlined a number of steps to convert the slogan — 'JAI VIGYAN' into action by making the following specific suggestions for consideration of the Scientific community, industry and policy makers in the Government to: (i) make science and scientific temper an integral part of national life (ii) reform science education at school level to promote creativity (iii) make science central to planning process (iv) enhance the intellectual and psychic income of our young scientists and recognise and respect the achievements of talented scientists

(v) synergise and create knowledge networks

(vi) promote R&D in and by industry

(vii) focus and concentrate on select areas to achieve global excellence and leadership

(viii) enhance the use of Information Technology through a national campaign

(ix) create an intellectual property movement

(x) debureaucratise scientific institutions

Initiatives have begun to link academic in stitutions, national laboratories and the indus try, more specifically, for instance, an action plan for reorienting the national laboratories under CSIR to address the basic issues of S&T
for common man, competiti venss of Indian in dustry, Value addition to endogenous resources
and attaining global leadership in science. Specific strategy papers with time and task targets are being drawn. Similarly, the Gov ernment in this budget have announced a new programme called Fund for Improvement of Infrastructure in Science and Technology (FIST). Special 'Swaran Jayanti Fellowships' are going to be announced very shortly for Promising young Scientists below the age of 40 years to enable them to perform at world class level..... "

The words "Results of the" are to be added before the words "Sepcial Swaran Jayanti Fellowships" in the last sentence.

[Placed in library. *See* No. LT-94I/98]

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल) : करेक्शन तो छोटा-मोटा था। लेकिन मंत्री महोदय ने जो ओरिजनल 12 जून का आन्सर था वह सदन को पूरा पढ़कर सुनाया जबकि यहां पर सिर्फ करेक्शन पढ़ने से ही चल जाता। उससे सप्लीमेंट्री अराइज करता हैं। वह स्टार्ड क्वेश्चन था। हमारा सप्लीमेंट्री आपके करेक्शन के ऊपर हैं। आपके पूरे क्वेशन के ऊपर नहीं हैं। आपने पहले बताया था कि फेलोशिप अनाउंस करेंगे। यह ओरिजनल क्वेशन में था। आज करेक्शन में आप बताते हैं कि रिजल्ट्स फेलोशिप के लिए कब परीक्षा या इन्टरव्यूज लिए गए और ये रिजल्ट्स अब तक अनाउंस हुए या नहीं? अगर नहीं हुए तो कब किए जा रहे हैं?

†**شری محمد سلیم:** کریکشن تو چھوٹا موٹا تھا۔ لیکن منتری مہودے نے جو اوریجنل ۱۲ جون کا جواب تھا وہ سدن کو پورا پڑھکر سنایا جبکہ یہاں پر صرف کریکشن پڑھنے سے ہی چل جاتا جبکہ اس سے سپلیمنٹری ارائز کرتا ہے۔ وہ اسٹارٹ کوئشچن تھا ہمارا سپلیمنٹری آپکے کریکشن کے اوپر ہے۔ آپکے پورے کوئشچن کے اوپر نہیں ہے۔ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ " فیلو شپ" اناؤنس کریں گے۔ یہ اوریجنل کویشچن ہے آپ آج کریکشن میں بتاتے ہیں کہ رزلٹ وڈ بی اناؤنسڈ" میرا سوال یہ ہے کہ اسپشیل فیلو شپ کے لئے کب پریکشا یا انٹرویو لئے گئے اور یہ رزلٹ اب تک اناؤنس ہوئے یا نہیں آگیں نہیں ہوئے تو کب کئے جا رہے ہیں۔

†[]ITransilteration in Arabic Script

डा. मुरली मनोहर जोशी : देखिए, इसके लिए देश भर के वैज्ञानिकों से आवेदन प्राप्त किए गए थे। उसमें पहले एक स्क्रीनिंग कमेटी ने उनकी विधिवत् स्क्रीनिंग की। उसमें से कुछ उन्होने शार्ट लिस्ट किए। उसके बाद एक दूसरी कमेटी ने उनकी स्क्रीनिंग की। अब उसके रिजल्ट्स तैयार हैं। मेरा ख्याल हैं हम एक या दो दिन में सदन के सामने ही वे रिजल्ट्स रखेंगे क्योंकि मैंने आदेश दिया हैं कि वे रिजल्ट्स सदन को मालूम होने चाहिए। तब उस संबंध में अगर आप कोई जानकारी लेना चाहेंगे वह हम आपको पूरी तौर पर देंगे।

श्री मोहम्मद सलीम : मेरा प्रश्न यह था कि कब ये एप्लीकेशन्स इन्वाइट की गयीं? मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया। दो तीन दिन के अंदर रिजल्ट्स निकल जाएंगे यह बता दिया लेकिन फर्स्ट पार्ट अगर नहीं बताते हैं तो सिचुएशन पता नहीं चलेगी। आज के दिन का पहला प्रश्न मैं सी.बी.एस.सी. के बारे में पूछा और कहा कि सेंट्रल बोर्ड के लाखों लोग इम्तिहान देते हैं और हम रिजल्ट्सं निकाल देते हैं। इसलिए जो यंग साइंटिस्ट्स हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं उनको आपको उत्साह देना चाहिए। जय विज्ञान का सिर्फ नारा देने से नहीं चलेगा, सिर्फ आधे पेज का विज्ञापन देने से नहीं चलेगा, रंगीन बुकलेट छापने से नहीं चलेगा।

†**शरी मोहम्मद सलीम:** मेरा सवाल यह था कि कब यह एप्लीकेशन इनवाइट की गई। मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया। दो तीन दिन के अंदर रिजल्ट्स निकल जाएंगे। यह बता दिया लेकिन पहला हिस्सा अगर नहीं बताते हैं तो सजेशन पता नहीं चलेगा। आज के दिन का पहला सवाल मैंने सी.बी.एस.सी. और आई.सी.एस.डी. के बारे में पूछा था और कहा कि सेन्ट्रल बोर्ड से लाखों लोग एग्जाम देते हैं और हम रिजल्ट निकाल देते हैं। इस लिए जो इंजीनियरिंग साइंटिस्ट हैं जो फर्स्टेड हैं उनको आपको इंसेंटिव देना चाहिए। जय विज्ञान का सिर्फ नारा देने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ आधे पेज का विज्ञान देने से नहीं चलेगा। रंगीन बुक लेट छापने से नहीं चलेगा।

आप एक कमेटी बनाएं, फिर दूसरी कमेटी बनाएं, फिर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो इसको तो जरा साइंटिफिक कीजिए, टैक्नोलीजी का इतना एंडवासमेंट है हफ्ते में, दस दिन में, बीस रोज में कब आप एप्लीकेशंस इन्वाइट किए थे और अब आप रिजल्ट्स निकालेंगे इसे देखेंगे तब यह पता चलेगा कि आप कितनी तेजी से काम कर रहे है?

†**शरी मोहम्मद सलीम:** आप एक कमेटी बनाइं। पहर दूसरी कमेटी बनाइं। पहर स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो इसको तो जरा साइंटिफिक कीजिए।

†[]Transliteration in Arabic Script

टैक्नोलोजी का इतना एडवांसमेंट है हफ्ते में दस दिन में बीस रोज में कब आप एप्लीकेशन इनवाइट किए थे और कब आप रिजल्ट निकालेंगे। इसे देखेंगे तब यह पता चलेगा कि आप कितनी तेजी से काम कर रहे हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : देखिए ये आवेदन गत वर्ष 1997 में ही आहूत किए गए थे। उसके पश्चात् यह वैज्ञानिक दृष्टि से छान-बीन करना इसके लिए परमावश्यक हैं। प्रोजैक्ट्स हैं, उनकी तरफ से प्रस्ताव हैं । वह सामान्य सी उत्तर पुस्तिका नहीं है। उस पर बाकायदा इंटरव्यू किया गया, क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टीजियस फेलोशिप्स है। पच्चीस हजार रूपये प्रति मास हैं। इसलिए इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता हैं, क्योंकि किसी प्रकार से भी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति उसमें वंचित न रह जाए और कम स्तर का व्यक्ति उसको पा न जाए, इसलिए देश के प्रमुख वैज्ञानिक ने दो बाद इसकी छानबीन की। उनके नाम, उनके पते और उन्होने कब किया, यह जानकारी मैं आपको बाद में प्राप्त करा सकूंगा, क्योंकि मुझे इस समय वह जानकारी नहीं हैं। ....(**व्यवधान**)....

श्री मोहम्मद सलीम : आप कह कर मानते भी नहीं हैं ....(**व्यवधान**)....

†**शरी मोहम्मद सलीम:** आप कहकर मानते भी नहीं हैं "मदाखलत"...

डा. मुरली मनोहर जोशी : जी नहीं ....(**व्यवधान**)....

श्री मोहम्मद सलीम : एक साल से ....(**व्यवधान**)....

†**शरी मोहम्मद सलीम:** एक साल से..."मदाखलत"...

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह तो मैंने बता दिया ....(**व्यवधान**)....

श्री मोहम्मद सलीम : फेलोशिप की एप्लीकेशंस को प्रोसैस करने के लिए ....(**व्यवधान**)....

†**شری محمد سلیم:** فیلوشپ کی اپلیکیشن کو پروسیس کرنے کے لئے..."مداخلت"...

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं यह कह सकता हूं कि इसमें आवश्यक विलम्ब नहीं हैं क्योंकि 600 या 700 वैज्ञानिकों में से स्क्रीन करना और फिर उनके साथ इंटरव्यू दो-दो बार करना, यह एक अपने आप में बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है और मैं ऐसा समझता हूं कि खोज-बीन करके ठीक परंपरा बनाना जरूरी है। यह पहला चांस हैं इसलिए इसके बारे में विधिवत् स्टैडड्र्ज को नार्मलाइज़ करने की आवश्यकता हैं। एक बार यह स्तर तय हो जाता हैं कि इसमें यह स्तर रहेगा फिर आगे के लिए यह कार्यक्रम करना सुनिश्चित हो जाता हैं। स्कीम एनांउस होती हैं, बजट पास होता हैं, पैसा रिलीज़ होता हैं, उसके बाद विज्ञापन होते हैं। देश भर से तमाम लोगों से प्रोजैक्ट्स आते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि आपा प्रोजैक्ट बनाइये तो उसके लिए समय देना पड़ता हैं। दो महीने, तीन महीने उनको समय लगता हैं। कोई प्रयोगिक प्रोजैक्ट्स बनाता हैं, कोई थ्योरेटिकल प्रोजैक्ट्स बनाता हैं। विभिन्न विषय हैं, उनको कंपेयर करना पड़ता हैं। ऐसा नहीं हैं कि केवल एक ही सब्जैक्ट हैं। विज्ञान के विभिन्न हैं इसलिए अलग-अलग दृष्टि से उनको स्क्रीन करना पड़ता हैं स्केनिंग करना पड़ता है। इसलिए मैं यह नहीं मानता कि इसमें अनावश्यक विलम्ब हुआ है। लेकिन अगर सम्माननीय सदस्य के पास कोई ऐसी सूचना हैं कि इसमें बहुत जान-बूझ कर विलम्ब हुआ हैं तो वह अवश्य मेरे नोटिस में लाएं।

श्री ब्रतीन सेनगुंप्त .... (पश्चिमी बंगाल) **:** महोदय, जान-बूझ कर विलंब की बात नहीं हैं।

†[ ]Transilteration in Arabic Script

Various Governments appointed screening committees. They invited applications and that was in December, 1997. Six months have elapsed. There has also been a reduction of Rs. 18 crores in the Budget of the Ministry of Science and Technology. The allocations to the Department of Biotechnology and the Council for Scientific and Industrial Research have stagnated. Can the development of science, as the hon. Minister has pointed out,...

MR. CHAIRMAN: This does not arise out of the Minister's clarification...*{Interruptions)* The first part of your point is all right but not the other one.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Memorandums of Understanding (1998-99) between Govt of India and Central Warehousing Corporation, and Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Ltd.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILISERS AND MINISTER OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Sir I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Food and Consumer Affairs, Department of Food and Civil Supplies) and Central Warehousing Corporation, for the year 1998-99. [Placed in Library, *See* No. LT-1047/98]

(ii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals) and Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited, for the year 1998-99.

[Placed in Library *See* No. LT-1050/98]